हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 182 लखनऊ, शुक्रवार 27 फ़रवरी 2026 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

डीजीसीए के नए नियम : बुकिंग के 48 घंटे के अंदर टिकट रद्द किया तो पूरा रिफंड, क्या है 7 से 15 दिन की शर्त?

बीएनई

नई दिल्ली। विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन टिकट रिफंड नियमों में संशोधन किया है। अब यात्री हवाई टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या बदल सकते हैं, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों। डीजीसीए ने यात्रियों के अनुकूल संशोधित नियम जारी किए हैं। इसके तहत एयरलाइन को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि यात्री टिकट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर अपने नाम में कोई गलती दिखाए और टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो, तो इसका कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

डीजीसीए ने क्या कहा?

डीजीसीए ने कहा, यदि टिकट ट्रैवल एजेंट या पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई है, तो रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि हैं। एयरलाइन यह सुनिश्चित करें कि रिफंड प्रक्रिया 14 कार्यदिवसों के भीतर पूरी हो। इसके अलावा, यात्री या उसके परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा आपात स्थिति के कारण टिकट रद्द करने की शर्तों में भी बदलाव किए गए हैं। यह संशोधन इसलिए किया गया है, क्योंकि पिछले समय में यात्रियों की शिकायतें बढ़ रही थीं कि उन्हें समय पर रिफंड नहीं मिल रहा। टिकट रिफंड का मुद्दा दिसंबर 2025 में इंडिगो की उड़ानों में बाधा के दौरान भी सामने आया था, जब विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन को निर्देश

दिया था कि रिफंड को तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए। संशोधित नियम 24 फरवरी को जारी किया गया।

एयरलाइन को प्रदान करना होगा लुक–इन विकल्प

अब एयरलाइन को यात्रियों को टिकट बुकिंग के 48 घंटे के लिए लुक–इन विकल्प प्रदान करना होगा। इस अवधि में यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकता है, बस संशोधित उड़ान के लिए सामान्य प्रचलित किराए का भुगतान करना होगा।

किन उड़ानों के लिए नहीं होगी यह सुविधा?

डीजीसीए ने कहा कि यह सुविधा उन उड़ानों के लिए उपलब्ध नहीं होगी, जिनकी प्रस्थान तिथि बुकिंग की तारीख से कम से कम सात दिन (घरेलू उड़ान) और 15 दिन (अंतरराष्ट्रीय उड़ान) दूर है, यदि टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक की गई हो। 48 घंटे की अवधि समाप्त होने के बाद यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा और यात्री को संशोधन या रद्द करने के लिए संबंधित शुल्क देना होगा।

नाम में गलती पर अतिरिक्त शुल्क का दावा नहीं कर सकती एयरलाइन

डीजीसीए ने कहा कि यदि टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक की गई हो और यात्री ने बुकिंग के 24 घंटे के भीतर अपने नाम में गलती बताई हो, तो एयरलाइन किसी भी अतिरिक्त शुल्क का दावा नहीं कर सकती। चिकित्सा आपात स्थिति में टिकट रद्द होने पर यदि यात्री या उसी पीएनआर (यात्री का नाम और यात्रा का रिकॉर्ड) पर उसका परिवार अस्पताल में भर्ती होता है, तो एयरलाइन रिफंड या क्रेडिट शेल दे सकती है। अन्य मामलों में रिफंड तभी मिलेगा, जब एयरलाइन के एयरोस्पेस मेडिसिन विशेषज्ञ या डीजीसीए पैनल के विशेषज्ञ से यात्री की यात्रा योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हो।

डीजीसीए ने कर्मचारियों की भर्ती का लिया निर्णय

विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को कर्मचारियों की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है। उसने एयरवर्थिनेस, एयर सेफ्टी और अन्य निदेशालयों के लिए 38 कंसल्टेंट्स भर्ती करने का निर्णय लिया है। सरकारी नोटिस के अनुसार, विमानन योग्यता(एयरवर्थिनेस) निदेशालय में 24 और उड्डयन सुरक्षा (एयर सेफ्टी) निदेशालय में 6 कंसल्टेंट्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय संबंध और कानूनी मामलों के निदेशालय (डीआईआरएलए) में पांच सीनियर कंसल्टेंट्स और 2 कंसल्टेंट्स की भर्ती की जाएगी। डीजीसीए उड़ान प्रशिक्षण निदेशालय में भी कंसल्टेंट्स की भर्ती करेगा। सभी कंसल्टेंट्स कुछ शर्तों के साथ अनुबंध के आधार पर एक साल के लिए भर्ती किए जाएंगे। आवेदनकर्ताओं की अधिकतम आयु 63 वर्ष निर्धारित की गई है। नियामक को कर्मियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लगभग आधे पद खाली हैं। पांच फरवरी क विमानन मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि 15 जनवरी तक नियामक में 1,630 स्वीकृत पद थे, जिनमें से 787 पद खाली थे। कुल पदों में से 441 पद (26 तकनीकी और 15 गैर–तकनीकी) 2022 से 2024 के बीच डीजीसीए के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में बनाए गए थे। मंत्रालय ने कहा कि रिक्तियों को भरने के लिए समय–समय पर पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।

सीबीआई को मिली बड़ी कामयाबी, दुबई से भारत लाया गया भगोड़ा अनिल कुमार रेड्डी

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। भारतीय जांच एजेंसियों को विदेशों में छिपे अपराधियों को पकड़ने में लगातार सफलता मिल रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को इंटरपोल की मदद से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में छिपे वांछित भगोड़े अनिल कुमार रेड्डी को भारत लाने में सफलता मिली है। यह अपराधी आंध्र प्रदेश में कई गंभीर मामलों में आरोपी है। अनिल कुमार रेड्डी पर धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी जैसे कई गंभीर आरोप हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। वह कानून से बचने के लिए यूएई में जाकर छिप गया था। आंध्र प्रदेश पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने 5 सितंबर 2022 को अनिल रेड्डी के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी करवाया था। सीबीआई की खास यूनिट ने विदेश मंत्रालय और अबू धाबी के अधिकारियों के साथ मिलकर यह कार्रवाई की। इसी रेड नोटिस के आधार पर यूएई के अधिकारियों ने अनिल रेड्डी को अपने देश में पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद यूएई ने उसे भारत को सौंपने का फैसला किया। गुरुवार को दुबई पुलिस की एक टीम उसे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेकर आई। यहां सभी जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे आंध्र प्रदेश पुलिस की टीम को सौंप दिया गया। यह कोई पहला मामला नहीं है। पिछले महीने भी सीबीआई ने मलेशिया के साथ मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन किया था। तब इंटरपोल रेड नोटिस वाले तीन अपराधियों को भारत से मलेशिया भेजा गया था। इनके नाम श्रीधरन सुब्रमण्यम, प्रतीफकुमार सेल्वराज और नवींद्रन राज कुमारसन हैं। मलेशियाई अधिकारियों के अनुसार, ये तीनों संगठित अपराध के गंभीर मामलों में शामिल थे। इन पर गैरकानूनी तरीके से पैसा और ताकत हासिल करने का आरोप था। ये तीनों यूनाइटेड किंगडम से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे। लेकिन रेड नोटिस होने के कारण इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें भारत में घुसने नहीं दिया। इसके बाद मलेशिया ने भारत से इन अपराधियों को वापस भेजने का अनुरोध किया। 25 जनवरी को रॉयल मलेशिया पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंची। सीबीआई और दूसरी भारतीय एजेंसियों के तालमेल से तीनों अपराधियों को सुरक्षित तरीके से मलेशियाई टीम को सौंप दिया गया।

संक्षिप्त समाचार

यौन शोषण मामले में फसें अविमुक्तेश्वरानंद पर लटकी जेल की तलवार, सुनवाई पर बोले–आरोप बेबुनियाद

एजेंसी

प्रयागराज। बटुकों के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय के सूत्रों ने बताया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट नंबर 72 में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गयी है। इस बीच, सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी–झूंसी) विमल किशोर मिश्रा ने बताया कि कथित पीड़ित बटुकों का मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है और रिपोर्ट सीलबंद लिफाफा में जांच अधिकारी को सौंप दी गई है। हालांकि, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट की विषयवस्तु पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि सीलबंद लिफाफे में मेडिकल रिपोर्ट अदालत के समक्ष रखी जाएगी।

यूपी सरकार व यामानाशी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर समझौता

रोड शो में योगी ने दिया निवेश का आमंत्रण

यूपी और यामानाशी के बीच सहयोग भारत–जापान संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाएगा : योगी

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। जापान दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और बड़ी सफलता हासिल की है। यूपी सरकार ने जापान के यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारतीय छात्रों को जापान में उच्चस्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यामानाशी में आयोजित यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो में प्रदेश की नई विकास नीति और निवेश संभावनाओं को वैश्विक उद्योग जगत के सामने प्रमुखता से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने शासन की कार्यशैली रिएक्टिव से बदलकर प्रोएक्टिव बनाया है। यही परिवर्तन आज प्रदेश की तेज आर्थिक प्रगति का आधार बना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश व यामानाशी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थानों के छात्र जापान में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और इस तकनीक को प्रदेश की इंडस्ट्रीपब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा क्षेत्र में लागू किया जाएगा। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में कई जी 2जी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और जी 2बी गवर्नमेंट टू बिजनेस स्तर की बैठकों में भाग लिया, जहां भारतीय दूतावास के सहयोग से जापानी उद्योग समूहों से व्यापक संवाद हुआ। उन्होंने यामानाशी प्रशासन को सक्रिय पहल कर निवेश संवाद को आगे बढ़ाने के लिए विशेष धन्यवाद दिया।मुख्यमंत्री ने रोबोटिक्स को भविष्य की प्रमुख तकनीक बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में रोबोटिक्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की व्यवस्था की है। 25 करोड़ की आबादी

वाला उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां प्रकृति की विशेष कृपा है। भारत की सबसे उर्वर भूमि, सर्वाधिक जल संसाधन, विशाल मानव संसाधन और आध्यात्मिक–सांस्कृतिक विरासत उत्तर प्रदेश को विशेष पहचान देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है और पिछले नौ वर्षों में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय तथा अर्थव्यवस्था तीन गुना करने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन व्यवस्था में आए परिवर्तन का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले समस्याओं पर प्रतिक्रिया देने वाली व्यवस्था थी, जबकि अब उत्तर प्रदेश ने प्रोएक्टिव गवर्नेंस मॉडल अपनाया है। निवेश आकर्षित करने, उद्योगों को सुविधा देने, नई तकनीक अपनाने और वैश्विक साझेदारी बढ़ाने की दिशा में सरकार लगातार पहल कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी प्रांत के राज्यपाल एवं उनकी टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जापान सरकार और यामानाशी प्रशासन ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को उनके विशिष्ट क्षेत्रों को नजदीक से समझने और उद्योग जगत से सीधे संवाद का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। इंडस्ट्री लीडर्स तथा भारतीय समुदाय के लोगों का स्वागत किया। दिसंबर 2024 में यामानाशी के राज्यपाल उत्तर प्रदेश आए थे और उसके बाद दोनों सरकारों के बीच निरंतर संवाद, फॉलो–अप तथा प्रतिनिधिमंडलों के आदान–प्रदान से यह सहयोग नई दिशा में आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि बिजनेस डेलीगेशन के अध्ययन और रिपोर्ट के बाद आज

राज्यपाल के आमंत्रण पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल यामानाशी पहुंचा है, जहां सहयोग को ठोस रूप मिला है।इस अवसर पर यामानाशी प्रांत के राज्यपाल कोटारो नागासाकी, उपराज्यपाल जुनिचि इशिदरा, उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', जापान में भारत की राजदूत नगमा मलिक समेत यूपी सरकार के प्रतिनिधिमंडल के अधिकारी, यामानाशी के इंडस्ट्री लीडर्स तथा भारतीय समुदाय से जुड़े लोग उपस्थित रहे।

ईडी के सामने पेश हुए अनिल अंबानी, जब्त हो चुका है 3716 करोड़ का बंगला

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। अनिल अंबानी को गुरुवार (26 फरवरी 2026) को कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए (ईडी) के सामने पेश हुए। 66 वर्षीय उद्योगपति सुबह करीब 10.30 बजे केंद्रीय दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। इससे पहले अगस्त 2025 में भी उनसे पूछताछ की गई थी। यह जांच उनकी समूह कंपनी (आरसीओएम) से जुड़े कथित 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक लोन फ्रॉड से संबंधित है। आरोप है कि लोन राशि के इस्तेमाल में अनियमितताएं हुईं। ईडी ने हाल ही में इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। बताया गया है कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उठाया गया। एजेंसी ने अदालत को जानकारी दी है कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) से जुड़े बैंक लोन फ्रॉड और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए तीन अलग–अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले दर्ज किए गए हैं। इससे एक दिन पहले ईडी ने मुंबई स्थित अनिल अंबानी के 3,716 करोड़ रुपए मूल्य के आवास 'अबोड' को एंटी–मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अस्थायी रूप से अटैच किया। यह 17 मंजिला और करीब 66 मीटर ऊंची इमारत मुंबई के पाली हिल इलाके में स्थित है। रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्ष 2000 के आसपास यह प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। मामले में जांच जारी है और ईडी संबंधित दस्तावेजों व वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही है।

सीमांचल से चुन–चुनकर निकाले जाएंगे घुसपैठिए, अररिया में अमित शाह का बड़ा ऐलान

बीएनई

अररिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को बिहार के अररिया जिले में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की लेटी और इंदरवा सीमा चौकियों पर कई परियोजनाओ का उद्घाटन और ई–शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने भारत–नेपाल सीमा की सुरक्षा और सीमांचल में जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों पर कड़ा संदेश दिया। अमित शाह ने अपने संबोधन में साफ किया कि केंद्र सरकार बिहार के सीमांचल क्षेत्र को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए एक श्रनिर्णायक अभियानश शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को हटाने का मतलब केवल मतदाता सूची से नाम काटना नहीं है, बल्कि उन्हें भारतीय धरती से पूरी तरह बाहर करना है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में होने वाले सभी अवैध कब्जों और निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा। घुसपैठ न केवल चुनावों को प्रभावित करती है, बल्कि गरीबों के हक का राशन और युवाओं

के रोजगार भी छीनती है। भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने जवानों को सावधान किया। उन्होंने कहा कि भले ही पड़ोसी देश मित्र है, लेकिन देशद्रोही तत्व इस खुले रास्ते का फायदा उठाकर भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने एसएसबी को अपनी खुफिया नेटवर्किंग मजबूत करने और सीमावर्ती गांवों के निवासियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की सलाह दी। अमित शाह ने दावा किया कि घुसपैठ के कारण पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार की जनसांख्यिकी में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए विश्वास जताया कि वहां भाजपा की सरकार बनते ही सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा किया जाएगा और घुसपैठियों को बाहर निकालना प्राथमिकता होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान किताब पर लगाया प्रतिबंध, जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

एजेंसी

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की कक्षा आठ की उन किताबों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक अध्याय शामिल है। न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह न्यायपालिका को बदनाम करने के इरादे से की गई सुनियोजित साजिश है, साथ ही अदालत ने भ्रष्टाचार पर अध्याय से संबंधित कक्षा आठ की सभी किताबों, उनकी प्रतियों और डिजिटल स्वरूपों को जब्त करने का आदेश दिया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, उन्होंने ऐसा आघात किया है।

मिर्जापुर दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, निर्माणाधीन मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण

बीएनई

मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मिर्जापुर के देवरी क्षेत्र का दौरा किया। यहां पर राज्यपाल ने यहां निर्माणाधीन मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया और कार्य की प्रगति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया। इसके बाद उन्होंने

उपस्थित बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए और उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति, जिला प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों और शैक्षणिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा, छनाबे विधायक रिंकी कोल, मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल, जिला कोऑपरेटिव अध्यक्ष जगदीश पटेल, अपना दल (एस) नेता दुर्गेश पटेल और हर्षित पटेल मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार, पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक, मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार, डीएफओ समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

संपादकीय

ए.आई. शिखर सम्मेलन, खुद को बेपर्दा करती कांग्रेस

कहते हैं 'घर का भेदी लंका ढाए'– आज जब दुनिया भारत को एक उभरती हुई आर्थिक, डिजिटल और कूटनीतिक शक्ति के रूप में देख रही है, तब देश के भीतर का एक राजनीतिक वर्ग जैसे हर राष्ट्रीय उपलब्धि और अपनी जड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने पर आमादा दिखाई देता है। भारत की अर्थव्यवस्था, डिजिटल संरचना और कूटनीतिक सक्रियता में हाल के वर्षों में जो परिवर्तन दिखाई दिया है, उसने वैश्विक स्तर पर देश की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित किया है। कृत्रिम बुद्धिमता (ए.आई.) जैसे उभरते क्षेत्रों में नीति–निर्माण और तकनीकी विकास को लेकर भारत की पहल इसी व्यापक परिवर्तन का हिस्सा है। दिल्ली में 16 से 20 फरवरी, 2026 के बीच आयोजित 'ए.आई. इंपैक्ट समिट 2026' इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसका उद्देश्य केवल तकनीकी सहयोग नहीं, बल्कि ए.आई. के नैतिक और लोकतांत्रिक उपयोग पर वैश्विक सहमति विकसित करना भी था। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व, विशेषकर उसके शीर्ष नेता और नेता–प्रतिपक्ष (लोकसभा) राहुल गांधी और उनसे प्रेरित कार्यकर्त्ताओं ने इस अवसर को भी ओछी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। असहमति और विरोध लोकतंत्र में प्राणवायु हैं, परंतु भारत मंडपम के भीतर युवा कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं द्वारा किया गया 'अर्धनग्न प्रदर्शन' कोई स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्य नहीं, बल्कि राजनीतिक–वैचारिक खीझ के साथ व्यक्तिगत वैमनस्य का भद्दा प्रदर्शन था। स्वयं राहुल गांधी ने अपने आरोपी कार्यकर्त्ताओं को 'बब्बर शेर' कहकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को घेरने के लिए वे इसी तरह देश की साख को दांव पर लगाते रहेंगे। पूरे घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे वैचारिक खोखलेपन का प्रतीक बताया है, तो समाजवादी पार्टी सहित कुछ अग्रिम भाजपा–विरोधी दलों ने भी कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं की इस फूहड़ता से दूरी बना ली है। भारत की छवि को धूमिल और कलंकित करने की यह औपनिवेशिक मानसिकता नई नहीं है। वर्ष 1927 में अमरीकी लेखिका कैथरीन मेयो ने अपनी पुस्तक 'मदर इंडिया' में भारतीय समाज में व्याप्त समस्याओं–जातिवाद, बाल–विवाह, स्वच्छता की कमी आदि को इस तरह प्रस्तुत किया कि मानो भारत स्वशासन के योग्य ही नहीं है। लेखिका का मत था कि 'आंतरिक विकृतियों' से ग्रस्त समाज राजनीतिक स्वतंत्रता के लायक नहीं है। उस किताब को गांधीजी ने 'नाली निरीक्षक की रिपोर्ट' कहकर खारिज कर दिया था। गांधीजी का पक्ष था कि समाज की कमियों को भीतर से सुधारा जा सकता है और यह आंतरिक दायित्व है, न कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उछालकर अपने ही राष्ट्र की साख गिराई जाए। आज विडंबना यह है कि गांधीजी की विरासत पर स्वघोषित दावा करने वाला कांग्रेस नेतृत्व स्वयं उसी औपनिवेशिक मानसिकता से जकड़ा है, जहां राजनीतिक द्वेष में एक घटना को भारत के अपने वैश्विक आयोजन की विफलता का प्रमाण मानकर प्रस्तुत किया जा रहा है। ए.आई. शिखर सम्मेलन में एक निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदघ्शत 'रोबोटिक डॉग', जोकि वास्तव में चीन निर्मित था और उस शैक्षणिक संस्था ने अपने छात्रों की उपलब्धि के रूप में पेश करके दिखाया था, उसे आधार बनाकर राहुल गांधी ने पूरे आयोजन को 'अव्यवस्थित' और 'तमाशा' करार दे दिया। एक निजी शिक्षण संस्थान, जिसे विवाद पश्चात कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया था, उसके अपराध को तथाकथित राष्ट्रीय 'अक्षमता' का प्रतीक बना देना वही मानसिकता है, जो कभी मेयो रूपी औपनिवेशिक शक्तियां भारतीय समाज के विरुद्ध इस्तेमाल करती थीं। अतीत में ऐसे अवसर भी आए, जब राजनीतिक मतभेदों के बावजूद राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी गई। 1994 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में उठाने की कोशिश की, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हाराव ने तबके विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सौंपा था। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए उस समय दलगत राजनीति को दरकिनार कर दिया गया और इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान का प्रस्ताव विफल हो गया। यह उस राजनीतिक परिपक्वता का उदाहरण था, जो आज दुर्लभ होती जा रही है। अब देश के जिस ए.आई. शिखर सम्मेलन में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एमेजॉन, ओपन ए.आई. और एंथ्रोपिक जैसी शीर्ष वैश्विक तकनीकी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सहित अनेकों राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे, लगभग 90 देशों ने 'नई दिल्ली घोषणा' को स्वीकार किया और 250 अरब डॉलर से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई हो, उसे कांग्रेस ने महज सरकारी 'जनसंपर्क अभियान' बताकर खारिज कर दिया। क्या यह सम्मेलन किसी राजनीतिक दल की बजाय भारत का नहीं था? इसी वैश्विक मंच पर भारतीय ए.आई. स्टार्टअप 'सर्वम' ने अपना नया 'इंडस ए.आई. चौट एप' जारी किया, जो 22 भारतीय भाषाओं में संचालित होता है। यह एप कंपनी के 105 बिलियन मानक वाले बड़े भाषाई ढांचे पर आधारित है।

विदेश भेजने की होड़ और बदलती मानसिकता

क्या सचमुच भारत में अवसर कम हैं या हम एक भ्रम में जी रहे हैं?

– डॉ. प्रियंका सौरभ

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय समाज में एक नई प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी हैकृ बेटे–बेटियों को विदेश भेजने की होड़। कभी पढ़ाई के नाम पर, कभी नौकरी के नाम पर, तो कभी बेहतर जीवन के सपने के साथ। कई परिवारों में यह एक उपलब्धि की तरह प्रस्तुत किया जाता है। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया है। किसी का कनाडा जाना, किसी का ऑस्ट्रेलिया या यूरोप जानाकृयह सब मानो सफलता की पहचान बन गया है। धीरे–धीरे यह धारणा बनती जा रही है कि यदि भविष्य बनाना है तो विदेश जाना ही पड़ेगा। लेकिन यह सवाल गंभीरता से पूछने की जरूरत है कि क्या वास्तव में भारत में अवसरों की कमी है। क्या इस देश में प्रतिभा के लिए जगह नहीं बची? या फिर हम स्वयं अपने देश की संभावनाओं को कम आंकने लगे हैं? भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तकनीक, उद्योग, सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप, शिक्षा और शोध के क्षेत्र में लगातार नए अवसर पैदा हो रहे हैं। दुनिया की बड़ी–बड़ी कंपनियाँ भारत में निवेश कर रही हैं। लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। छोटे शहरों और कस्बों से निकलकर युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं। ऐसे में यह मान लेना कि भविष्य केवल विदेश में ही है, एक अधूरी और जल्दबाजी वाली सोच लगती है। विदेश जाने की एक बड़ी वजह शिक्षा भी है। कई छात्र यह सोचकर विदेश जाते हैं कि वहाँ की पढ़ाई बेहतर है या वहाँ अवसर अधिक हैं। कुछ मामलों में यह सही भी हो सकता है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि कई छात्र केवल इसलिए विदेश चले जाते हैं क्योंकि उन्हें भारत में मनचाहे कॉलेज या कोर्स में प्रवेश नहीं मिल पाता। प्रतियोगिता कठिन है, सीटें सीमित हैं, और हर किसी को प्रतिष्ठित

संस्थानों में जगह नहीं मिल पाती। ऐसे में विदेश जाना एक विकल्प बन जाता है। लेकिन इस विकल्प को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बना देना चिंताजनक है। आज स्थिति यह हो गई है कि कई जगहों पर माता–पिता अपने बच्चों को विदेश भेजने को लेकर एक तरह का दबाव महसूस करते हैं। रिश्तेदारों, परिचितों और समाज के बीच यह दिखाने की कोशिश होती है कि उनका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है या काम कर रहा है। कई बार परिवार अपनी आर्थिक स्थिति से ज्यादा खर्च उठाकर भी बच्चों को विदेश भेज देते हैं। शिक्षा ऋण, कर्ज और आर्थिक बोझ के बावजूद यह निर्णय केवल इसलिए लिया जाता है क्योंकि समाज में इसे प्रतिष्ठा से जोड़ दिया गया है। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ाया है। इंटरनेट पर विदेश में रहने वाले युवाओं की चमकदार तस्वीरें दिखाई देती हैंकृखूबसूरत शहर, शानदार जीवनशैली, घूमना–फिरना, नए अनुभव। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे का संघर्ष अक्सर दिखाई नहीं देता। विदेश में जीवन आसान नहीं होता। वहाँ भी कठिन परिश्रम करना पड़ता है, अकेलेपन का सामना करना पड़ता है और कई बार ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिनकी कल्पना भारत में रहते हुए नहीं की जाती। लेकिन यह सच्चाई अक्सर तस्वीरों और वीडियो के पीछे छिप जाती है। समस्या विदेश जाने में नहीं है। समस्या उस मानसिकता में है जिसमें विदेश को सफलता का पर्याय बना दिया गया है। दुनिया को देखने, नई शिक्षा और अनुभव प्राप्त करने के लिए विदेश जाना एक अच्छा अवसर हो सकता है। कई भारतीय छात्र विदेश में उच्च शिक्षा लेकर नई तकनीक और ज्ञान प्राप्त करते हैं और बाद में देश के विकास में योगदान भी देते हैं। लेकिन जब यह निर्णय समझदारी के बजाय भीड़ का हिस्सा बनकर लिया जाता है, तब कई बार परिणाम निराशाजनक भी हो सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा वर्ग है। आज का युवा पहले से अधिक जागरूक, शिक्षित और तकनीक से जुड़ा हुआ है। स्टार्टअप संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। छोटे शहरों के युवा भी बड़े सपने देख रहे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। डिजिटल युग में अवसरों की सीमाएँ पहले जैसी नहीं रहीं। आज भारत में बैठकर भी दुनिया के साथ काम किया जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को सक्षम बनाएं। उन्हें ऐसी शिक्षा दें जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाए, उनमें कौशल विकसित करे और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति दे। अगर युवा योग्य होंगे तो उन्हें अवसर कहीं भी मिल सकते हैंकृभारत में भी और विदेश में भी। लेकिन यदि केवल स्थान बदलने से सफलता की उम्मीद की जाएगी, तो यह सोच लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। समाज को भी अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है। विदेश जाना न तो असंभव उपलब्धि है और न ही सफलता का एकमात्र रास्ता। उसी तरह भारत में रहना असफलता नहीं है। हमारे देश ने हर क्षेत्र में प्रतिभाएँ दी हैं–विज्ञान, साहित्य, खेल, राजनीति, उद्योग और तकनीक में। दुनिया के कई बड़े मंचों पर भारतीय अपनी पहचान बना चुके हैं। यह सब यहीं से शुरू हुआ है। एक और चिंता का विषय प्रतिभा का देश से बाहर जाना भी है। कई वर्षों तक "ब्रेन ड्रेन" की चर्चा होती रही है। हालांकि अब स्थिति बदल रही है और कई लोग विदेश से अनुभव लेकर वापस भी लौट रहे हैं। फिर भी यह जरूरी है कि देश का युवा अपने देश की संभावनाओं पर विश्वास बनाए रखे। अगर योग्य लोग ही देश से दूर चले जाएंगे, तो विकास की गति भी प्रभावित हो सकती है। माता–पिता, शिक्षक और समाजकृतीनों की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण है। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि सफलता किसी देश की मोहताज नहीं होती। असली पहचान मेहनत, ज्ञान और चरित्र से बनती है। विदेश जाना यदि शिक्षा और अनुभव के लिए है तो यह अच्छी बात है, लेकिन केवल दिखावे या सामाजिक दबाव के कारण लिया गया निर्णय कई बार भारी पड़ सकता है। आज जरूरत है संतुलित सोच की। हमें अपने युवाओं को यह बताना होगा कि दुनिया खुली है, अवसर हर जगह हैं, लेकिन अपने देश की ताकत और संभावनाओं को कम नहीं आंकना चाहिए। भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि संभावनाओं की एक विशाल भूमि है। यहाँ चुनौतियाँ भी हैं और अवसर भी। फर्क केवल दृष्टिकोण का है। अगर हम अपने बच्चों को योग्य, आत्मविश्वासी और मेहनती बनाएँगे, तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकताकृचाहे वे भारत में रहें या विदेश जाएँ। लेकिन यदि हम केवल भीड़ का हिस्सा बनकर निर्णय लेते रहेंगे, तो शायद हम अपने ही आत्मविश्वास को कमजोर करते रहेंगे। विदेश जाना विकल्प हो सकता है, लेकिन लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिएकृ योग्यता, आत्मनिर्भरता और सार्थक जीवन। जब यह सोच समाज में मजबूत होगी, तब शायद विदेश भेजने की अंधी दौड़ अपने आप धीमी पड़ जाएगी।

मां तुझे सलाम, यही है असली वंदेमातरम

–सर्वमित्रा सुरजन

अपने बेटे को जेल में देखकर भी मां कहे कि हमें आज भगत सिंह की जरूरत है, तो ऐसी मां को हजार सलाम, जो बिना घबराए अपने बेटे को न केवल हौसला दे रही हैं, बल्कि बाकी युवाओं को भी ऐसे अन्याय के खिलाफ खड़े होने का आह्वान कर रही हैं। ऐसी ही एक मिसाल उत्तराखंड के कोटद्वार से आई, जहां जिम प्रशिक्षक दीपक की मां ने उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की परवरिश दी। वंदे मातरम का असली मतलब अगर भाजपा के लोग समझते तो कभी उसे अपनी संकीर्ण मानसिकता के साथ राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन भाजपा के लिए वंदे मातरम का उद्घोष भी वैसा ही है, जैसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी मां के संघर्ष को बयां करें। देश से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पर नरेन्द्र मोदी ने न केवल अपनी गरीबी का रोना रोया, बल्कि अपनी मां के संघर्षों का जिक्र कर आंसू बहाए, ताकि सहानुभूति मिल सके। इसके बाद जन्मदिन पर कैमरे के कई एंगल्स के बीच उनके हाथ से प्रसाद खाना या उनके पैरों पर बैठना जैसे उपक्रम भी उन्होंने किए ताकि मां–बेटे के प्यार का राजनीतिक इस्तेमाल हो सके। हालांकि जब तक नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री रहे, उनकी मां का ऐसा सार्वजनिक जिक्र हुआ हो, याद नहीं पड़ता। क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें अपनी मां के करीब होने की जरूरत ज्यादा पड़ी, यह सोचने वाली बात है। नोटबंदी के फैसले को सही ठहराने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी मां को बैंक की कतार में भी खड़ा कर दिया था और जब उनके जीवन के आखिरी दिनों में जब वे आईसीयू में थीं, तब भी कई कैमरों के साथ नरेन्द्र मोदी आईसीयू में पहुंचे थे, यह भी सबने देखा है। उनकी मौत के बाद भी मां की ममता को राजनैतिक फायदे के लिए भुनाने की कोशिशें उन्होंने की, याद कीजिए कि बिहार चुनाव के वक्त वे गयाजी में उनका पिंडदान करने वाले थे, जबकि यह काम पहले उनके भाई वाराणसी में कर चुके थे। दो–दो बार पिंडदान कर मोदी न केवल अपनी दिवंगत मां का अपमान करते, बल्कि हिंदू धर्म का भी अनादर ही होता। लेकिन समरथ को नहीं दोष गुंसाईं को मोदी ने शायद कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया है कि वे कुछ भी करेंगे और सवाल नहीं उठेंगे। बहरहाल, मां के नाम को भुनाने का ताजा उदाहरण नरेन्द्र मोदी ने मेरठ में रेपिड मेट्रो के उद्घाटन पर दिया, जहां भाषण देने के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निकृष्ट से निकृष्टतम शब्दों का इस्तेमाल कर हमला किया, इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस के लोग उनकी मां को अपशब्द कहते हैं। जबकि बिहार चुनाव के दौरान हुए इस प्रकरण में कांग्रेस का हाथ है, ऐसा कहीं साबित नहीं हुआ है। लेकिन इस समय नरेन्द्र मोदी एपस्टीन फाइल्स, अमेरिका से ट्रेड डील, ऑपरेशन सिंदूर पर उठे सवाल, मनरेगा को खत्म करना, हरदीप पुरी को संरक्षण जैसे कई मुद्दों पर इतनी बुरी तरह घिरे हुए हैं कि उनकी बौखलाहट अब खुलकर जाहिर होने लगी है। मोदी को यह समझ नहीं आ रहा कि सार्वजनिक तौर पर रोने–धोने की चालाकी से अब सियासी फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग भी देश की हकीकत देख रहे हैं। और जिन्हें अब तक हकीकत नजर नहीं आई, उन्हें भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतार कर प्रदर्शन कर दिखा दिया कि मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इस प्रदर्शन की भाजपा समेत मीडिया के बड़े हिस्से ने खूब आलोचना की, लेकिन इसका कितना व्यापक असर हुआ है, ये मोदी सरकार की घबराहट ने जाहिर कर दिया। उसने पहले कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तार लोगों ने न डर दिखाया, न आत्मसमर्पण (सरेंडर) किया और न कॉम्प्रोमाइज्ड (दबाव में आकर समझौता) हुए। इसके बाद कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उसकी सार्वजनिक आलोचना की। कांग्रेस नेताओं को धिक्कारते हुए प्रधानमंत्री ने ये तक कह दिया कि इन्हें शर्म नहीं आती। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के तेवर ढीले नहीं हुए, बल्कि राहुल गांधी ने तो बाकायदा वीडियो जारी कर बता दिया कि असली शर्म क्या होती है और ये किसे आनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा श्मोदी जी, आप शर्म की बात करते हो? शर्म की बात मैं आपको बताता हूं। एपस्टीन फाइल में आपका, आपके मंत्री और आपके मित्र का नाम साथ में आना, ऐसे घिनौने अपराधी के साथ आपका नाम जुड़ा होना – ये शर्म की बात है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील में देश को बेच देना शर्म की बात है। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया।श राहुल ने अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस का जिक्र किया और कहा, पूरा देश जानता है कि अडानी केस ने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है। यह भाजपा और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। 14 महीनों से कोई कार्रवाई नहीं हुई– ये शर्म की बात है।श राहुल ने कहा, श्मोदी जी, आप अपने मित्रों अनिल अंबानी, अडानी और खुद के लिए जो उचित समझें, वो कीजिए। मैं और कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर देश की रक्षा करते रहेंगे– एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने न केवल नरेन्द्र मोदी को चेतावनी दे दी, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को भी संदेश दे दिया कि वो हर हाल में उनके साथ खड़े हैं। युवा कांग्रेस में इस नए जोश का दिखना जाहिर करता है कि जिस कांग्रेस मुक्त भारत का सपना लेकर मोदी सत्ता में आए थे, वो अब दूर की कौड़ी नहीं बल्कि असंभव ही है। राहुल गांधी का अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होना जाहिर बात है, लेकिन बड़ी बात ये है कि अब कार्यकर्ताओं के अभिभावक भी उनके साथ खड़े हो रहे हैं। जैसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को एआई समिट में प्रदर्शन का मास्टरमाइंड बताते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब उन्हें चार दिनों की रिमांड पर भी भेजा जा चुका है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में घबराने की जगह उनके माता–पिता अपने बेटे पर गर्व कर रहे हैं कि वो सही काम के लिए हिम्मत दिखा कर डटे रहे। उदय भानु चिब की मां ने कहा कि हमें आज भगत सिंह की जरूरत है।

राशिफल

मेष :– भावना से उद्वेलित मन निकट संबंधों के सुख–दुख के प्रति चिंतित होगा। पूर्वाग्रहवश संबंधियों के प्रति नकारात्मकता को न पालें। भविष्य संबंधी कुछ चिंताएं मन में नकारात्नक विचार ला सकती हैं।

बृषभ :– भौतिक महत्वकांक्षाएं अभाव का एहसास कराएंगी। परिजनों से कुछ भावनात्मक अपेक्षाएं कष्टकारी हो सकती हैं। अच्छी योजनाओ द्वारा महत्वपूर्ण कायरें को समयानुकूल पूर्ण करेंगे।

मिथुन :– भावनाओं पर नियंतण्ररख अपने दायित्वों के प्रति सजग होना प्रगति का सूचक है। बचकाना स्वभाव महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एकाग्रता का अभाव पैदा करेगा। शिक्षा–प्रतियोगिता में परिश्रम का लाभ मिलेगा।

कर्क :– महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अपनी पूर्ति हेतु मन पर दबाव बनाएंगी। कुछ नयी आकांक्षाएं मन पर प्रभावी होंगी। भौतिक–सुख साधन में व्यय संभव। परिजनों से किसी प्रकार की शिकायत पर खुलकर बात करें।

सिंह :– किसी श्रेष्ठजन के प्यार से मन प्रसन्न होगा। किसी की कटु वाणी मन को दुखित कर सकती है। उच्च महत्वकांक्षाएं व्यावसायिक क्षेत्र में अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित करेंगी। आलस्य कतई न करें।

कन्या :– नये संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। पारिवारिक वातावरण सुखद व उत्साहपूर्ण होगा। जीविका क्षेत्र में मन आर्थिक सुदृढ़ता हेतु प्रयत्नशील होगा। रोजगार में व्यस्तता रहेगी किंतु जरूरी कार्य समय से पूर्ण करें।

तुला :– कुछ नयी अभिलाषाएं आपको उत्साहित करेंगी। शासन–सत्ता की दिशा में केंद्रित लोगों को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। किसी महत्वपूर्ण दायित्व की पूर्ति हेतु समुचित व्यवस्था हेतु मन चिंतित होगा।

वृश्चिक :– किसी पुराने संबंध के प्रति विशेष निकटता की अनुभूति करेंगे। क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां अर्थिक सुदृढ़ता हेतु प्रेरित करेंगी। भावनाप्रधान मन रिश्तों से सहज ही प्रभावित हो जाता है।

धनु :– रोजगार क्षेत्र में आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं सार्थक होती हुई नजर आएंगी। श्रेष्ठजनों से नजदीकियां पैदा होंगी। व्यावसायिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कुछ प्रबल इच्छाएं आपको उद्वेलित करेंगी।

मकर :– सामाजिक गतिविधियों में आपकी क्रियाशीलता बढ़ेगी। अच्छी भावनात्मक अभिव्यक्ति से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा।

कुंभ :– पुरानी समस्याओं को हल कर सुख की अनुभूति करेंगे। शासन–सत्ता से जुड़े लोगों को लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। पूजा–पाठ में पूरा दिन मन केंद्रित होगा। नये दायित्वों की पूर्ति होगी।

मीन :– पिता के सहयोग से मुश्किल दिनों में राहत मिलेगी। बालसुलभता व असंयमित शब्दों का प्रयोग संबंधों में कटुता लाएगा। आकस्मिक नई आशंकाओं से प्रभावित मन कोई गलत निर्णय ले सकता है।

कार्नी के भारत दौरे में पंजाब दरकिनार, दोषी कौन?

मनिंदर सिंह गिल

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत दौरे का ऐलान किया है। वह भारत में मुंबई और नई दिल्ली में बिजनैसमैन और पॉलिटिकल लीडर्स से मिलेंगे, जहां कनाडा और भारत के बीच ट्रेड और एनर्जी एग्रीमैंट को बढ़ावा देने पर बातचीत होगी। कनाडा और भारत के बीच 2010 से चल रहे सी.ई.पी.ए. फ्री ट्रेड एग्रीमैंट की द्विपक्षीय बातचीत को और करीब लाने पर भी बातचीत हो रही है। कार्नी का भारत दौरा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत और कनाडा के रिश्ते बद से बदतर होते गए थे लेकिन कार्नी ने इन रिश्तों को वापस पटरी पर लाने की पहल की है। उन्होंने चुनाव कैंपेन के दौरान साफ कर दिया था कि वह भारत के साथ मजबूत रिश्ते चाहते हैं। कैनासकस (कनाडा) में हुए जी–7 समिट के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को न्यौता भेजकर कार्नी ने दिखा दिया था कि वह खालिस्तानी पार्टियों और उनके मीडिया साथियों के दबाव में नहीं आएंगे और उनके काम कनाडा और कनाडाई लोगों के हितों को सबसे पहले रखकर ही आगे बढ़ेंगे। इस दौरे की एक और खास बात यह है कि पहले जब भी कोई कनाडाई प्रधानमंत्री भारत आया, तो पंजाब भी इस दौरे में एक स्टॉपओवर रहा है। पॉल मार्टिन को छोड़कर, सभी प्रधानमंत्री अपने भारत दौरे के दौरान पंजाब आए लेकिन इस बार कार्नी के दौरे की जो डिटेल्स सामने आई हैं, उनसे यह साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री पंजाब में नहीं रुकेंगे। इस फैसले से कनाडा में रहने वाले पंजाबी समुदाय में चर्चा शुरू हो गई है। जब प्रधानमंत्री ऑफिस के स्टाफ से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मार्क कार्नी का दौरा आध्थक और राजनीतिक मुद्दों को ध्यान में रखकर प्लान किया गया है और वह अक्सर कनाडा में सांस्कृतिक मुद्दों में भी हिस्सा लेते हैं। इन सबके बावजूद, पंजाबी और सिख समुदाय में इस मामले को लेकर थोड़ी निराशा है लेकिन आज जब अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के एजैंडे में पंजाब को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो सिख कम्युनिटी और पंजाबी कम्युनिटी को मिलकर सोचना होगा कि पंजाब के हाशिए पर जाने की वजह कौन है। पंजाबी समुदाय ने पिछले 100 सालों में कनाडा में अपनी खास पहचान बनाई है और समाज के हर क्षेत्र में अच्छा नाम कमाया है। पंजाबी समुदाय कनाडा में राजनीतिक तौर पर भी बहुत काबिल है, लेकिन पिछले 4 दशकों से फिरकापरस्त खालिस्तानी पार्टियों द्वारा चलाया जा रहा हेट कैंपेन पंजाब और पंजाबियत का दुश्मन बनकर उभरा है। शायद ही किसी और संस्था या विचार ने पंजाब, पंजाबियत और अंतर्राष्ट्रीय पंजाबी समुदाय का इतना नुकसान किया हो, जितना इन बांटने वाली ताकतों ने किया है। कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, पंजाबी मूल के कुछ सांसद, जो खालिस्तानी पार्टियों के सपोर्टर हैं या उनसे वोट पाने के लिए बेचैन हैं, उन्होंने कार्नी का विरोध करना शुरू कर दिया, चाहे वह प्रधानमंत्री मोदी का कनाडा जी–7 का दौरा हो या भारत के साथ राजनीतिक और सुरक्षा संबंध सुलझाने की कोई पहल।

बाह्य ऋण, विकास और वैश्विक जिम्मेदारी : भारत की आर्थिक रणनीति

–अरुण डनायक

आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में बाह्य ऋण किसी भी राष्ट्र के लिए एक अपरिहार्य यथार्थ बन चुका है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। मध्य–आय जाल की स्थिति में विकास की गति बनाए रखने, अवसंरचना, उद्योग और सामाजिक क्षेत्र में निवेश तथा विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाह्य पूंजी की आवश्यकता बनी रहती है। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने बाह्य उधारी को अंधानुकरण नहीं, बल्कि एक सुविचारित नीति–उपकरण के रूप में अपनाया है। इसका उपयोग मुख्यतरू अवसंरचना, ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक विस्तार और वित्तीय स्थिरता के लिए किया गया है। विशेष रूप से, बाह्य वाणिज्यिक उधारी और आवश्यकता पड़ने पर आईएमएफ से प्राप्त ऋ णों ने निजी क्षेत्र को भुगतान–संतुलन बनाए रखने में सहायता दी, जिससे निवेश, उत्पादन क्षमता और रोजगार सृजन को बल मिला। संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी ऋ ण लेने की सीमित संभावना होती है, और अधिकांश बाह्य उधारी केंद्र सरकार के माध्यम से होती है , जिससे ऋ ण प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता को संस्थागत रूप से नियंत्रित रखा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, जून 2025 के अंत तक केंद्र और राज्यों का कुल बाह्य ऋ ण 747.2 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो सितंबर 2025 में हल्का घटकर लगभग 746 अरब डॉलर रह गयाकृअर्थात समग्र स्तर पर स्थिरता बनी रही। यह जून 2024 के 681.5 अरब डॉलर की तुलना में वार्षिक आधार पर 9.6 प्रतिशत अधिक है। दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही में बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) के माध्यम से उधारी प्रवाह में वृद्धि के संकेत मिलेय दिसंबर माह में अकेले 4.43 अरब डॉलर की नई ईसीबी जुटाई गई, जिससे अप्रैल–दिसंबर 2025 के दौरान कुल जुटाई गई राशि लगभग 27.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यह आंकड़े प्रवाह को दर्शाते हैं, न कि कुल बकाया स्टॉक को। इससे संकेत मिलता है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक अपनी पहुंच बनाए हुए हैं। ऋण राशि बढ़ने के बावजूद बाह्य ऋण–से–जीडीपी अनुपात मार्च 2025 के 19.1 प्रतिशत से घटकर 18.9 प्रतिशत रह गया है, जो दर्शाता है कि आर्थिक वृद्धि ऋ ण वृद्धि से तेज रही। यद्यपि केंद्रीय सरकार की सकल राजस्व प्राप्तियों (रुपए 34.96 लाख करोड़) की तुलना में बाह्य ऋण का स्तर ऊंचा प्रतीत होता है, फिर भी यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अभी जोखिम की सीमा के भीतर है। हाल के समय में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों के भारतीय शेयर बाजार से दूरी बनाए रखने की प्रवृत्ति के चलते बाह्य ऋण पर निर्भरता बढ़ने की संभावना बनी है, जिससे कंपनियों के लिए विनिमय–दर जोखिम का प्रबंधन और अधिक जटिल तथा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भारत का बाह्य ऋण संरचनात्मक रूप से सुरक्षित है। 82 प्रतिशत दीर्घकालिक, अल्पकालिक मात्र 18.1प्रतिशत, विदेशी मुद्रा भंडार से 93प्रतिशत से अधिक आच्छादन, ऋण–सेवा अनुपात केवल 6.6प्रतिशत तथा परिसंपत्ति–दायित्व अनुपात 79.25प्रतिशत होने के कारण तात्कालिक जोखिम न्यूनतम है। यद्यपि डॉलर पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भरता से विनिमय–दर जोखिम उत्पन्न होता है, लेकिन लगभग 700 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा 93 प्रतिशत से अधिक बाह्य ऋ ण का आच्छादन इस जोखिम को प्रभावी रूप से संतुलित करता है। रुपये की डॉलर के मुकाबले हाल की कमजोरी का असर सीधे कुल बाह्य ऋण की राशि पर नहीं पड़ता। इसका मुख्य प्रभाव ऋण–सेवा लागत, ब्याज भुगतान और भविष्य में ऋण के पुनर्भुगतान पर पड़ता है, जिससे कंपनियों और सरकार की वित्तीय योजना पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है। आम धारणा के विपरीत, भारत का बाह्य ऋण किसी एक देश या संस्था पर केंद्रित नहीं है। इसका स्वरूप विविध और संतुलित हैकृ 40 प्रतिशत वाणिज्यिक उधारी (अंतरराष्ट्रीय बांड और विदेशी बैंक), 22 प्रतिशत एनआरआई जमाएं, 11 प्रतिशत विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय संस्थाएं, 5 प्रतिशत जापान जैसे द्विपक्षीय ऋणदाताओं, तथा आईएमएफ की 21.6 अरब डॉलर की सीमित देनदारियां (मुख्यत: 1991 के संकट से जुड़ी)। भारत ने वर्षों से आईएमएफ से कोई नया कार्यक्रम ऋण नहीं लिया।

शिक्षकों ने ड्रोन बनाना सीखा

स्कूल शिक्षक दो दिवसीय प्रशिक्षण : फ्लाइट फ्रॉम स्क्रैच ड्रोन डिजाइन एंड मेकिंग वर्कशॉप कार्यक्रम किया गया आयोजन

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (AKTU), लखनऊ के इनोवेशन हब में स्कूल के शिक्षकों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का शीर्षक "Flight From Scratch: Drone Design – Making Workshop" था, जिसका उद्देश्य शिक्षकों को ड्रोन तकनीक की मूलभूत अवधारणाओं से लेकर उसके व्यावहारिक निर्माण तक की जानकारी प्रदान करना था, ताकि वे छात्रों को उभरती एयरोस्पेस और रोबोटिक्स तकनीकों के प्रति प्रेरित कर सकें। माननीय कुलपति प्रो. जे. पी. पांडेय के नेतृत्व एवं प्रो. बी. एन. मिश्रा (डीन – इनोवेशन और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एवं डायरेक्टर IHUPF) तथा केशव सिंह Finance officer एवं निदेशक IHUPF तथा डॉ. अनुज कुमार शर्मा (एसोसिएट डीन); महीप सिंह , CEO इनोवेशन हब के मार्गदर्शन में कार्यक्रम में ट्रेनर के रूप में Abul Kalam Khan, Founder – CEO – AirM, Spyral उपस्थित रहे। उन्होंने ड्रोन डिजाइनिंग, एयरोडायनामिक्स, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, मोटर एवं प्रोपेलर चयन, और ड्रोन असेंबली की संपूर्ण प्रक्रिया पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने शिक्षकों को बताया कि किस प्रकार Scratch ls Drone बनाने" की प्रक्रिया छात्रों में नवाचार, समस्या–समाधान कौशल और तकनीकी आत्मनिर्भरता विकसित करती है। कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य ड्रोन तकनीक की बुनियादी समझ विकसित करना

ड्रोन के विभिन्न घटकों (Frame, ESC,Flight Controller, Battery, Sensors आदि) का परिचय DIY (Do–It–Yourself) मॉडल के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण

ड्रोन के शैक्षणिक उपयोग – विज्ञान, गणित, भौतिकी और रोबोटिक्स में अनुप्रयोग

छात्रों में नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना.

शिक्षा में ड्रोन तकनीक का महत्व

1. प्रायोगिक अधिगम (Experiential Learning) :

ड्रोन निर्माण प्रक्रिया छात्रों को सिद्धांत से व्यवहार तक सीखने का अवसर देती है।

2. STEM शिक्षा को बढ़ावा :

ड्रोन डिजाइन में गणित, भौतिकी, प्रोग्रामिंग और इंजीनियरिंग का समन्वय होता है।

3. उद्यमशील दृष्टिकोण :

ड्रोन टेक्नोलॉजी कृषि, सर्वेक्षण, आपदा प्रबंधन, डिलीवरी और रक्षा क्षेत्रों में उपयोगी है, जिससे छात्रों को स्टार्टअप अवसरों की जानकारी मिलती है। विशेष सम्मान कार्यक्रम के प्रारंभ में IHUPF की CIO वंदना शर्मा ने मुख्य वक्ता अबुल कलाम खान को Plant Sapling भेंट कर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में सूरज वर्मा, मैनेजर; संजीव मिश्र, असिस्टन्ट मैनेजर एवं दीपक पटेल, टेक्नॉलजी असोशीएट प्रस्तुत रहे। शिक्षकों की प्रतिक्रिया कार्यक्रम में भाग लेने वाले शिक्षकों ने कार्यशाला को अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक बताया। उनका कहना था कि "Flight From Scratch" कार्यशाला ने उन्हें ड्रोन तकनीक की व्यावहारिक समझ प्रदान की, जिसे वे अपने विद्यालयों में STEM शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने में उपयोग करेंगे।

केशव मौर्य की सफल कूटनीति, जर्मनी से ही यूके के निवेशकों को जोड़ा

जर्मनी में सर्विस सेक्टर से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मिला अच्छा रिस्पॉन्स
यूके के निवेशकों ने यूपी में निवेश करने पर जताई सहमति
जर्मनी में 200 करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति
रेल इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीक में सहयोग बढ़ाएगा उत्तर प्रदेश

लखनऊ ब्यूरो

बर्लिन/लखनऊ। जर्मनी में चल रही रुचिकर एआई इंपैक्ट समिट के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निवेश कूटनीति की नई कार्यशैली अपनाते हुए अपनी पूर्व निर्धारित यूनाइटेड किंगडम यात्रा स्थगित कर दी। समिट की व्यस्तताओं और वैश्विक प्रतिनिधियों से लगातार संवाद के कारण उन्होंने जर्मनी से ही यूके के निवेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वन–टू–वन बातचीत की। इस वर्चुअल संवाद में निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर सकारात्मक सहमति जताई, जिसे प्रदेश के लिए अहम उपलब्धि माना जा रहा है। जर्मनी प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री को विशेष रूप से सर्विस सेक्टर में अच्छी संभावनाएं दिखीं। ड्रोन तकनीक, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्ट सिटी जैसे भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में अग्रणी जर्मन कंपनियों के साथ उनकी विस्तृत बैठकें हुईं। कंपनियों ने उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, बेहतर कनेक्टिविटी और बड़े बाजार को निवेश के लिए अनुकूल बताया। हालांकि हाई–टेक मैन्युफैक्चरिंग के साथ सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक रुचि देखने को मिली। आईटी सेवाएं, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थकेयर सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट से जुड़ी कंपनियों ने प्रदेश के विशाल उपभोक्ता आधार और कौशल संसाधन को निवेश का मजबूत आधार माना। इसी क्रम में यूके के निवेशकों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के औद्योगिक रोडमैप, सिंगल विंडो सिस्टम और त्वरित स्वीकृति प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी साझा की गई। बातचीत सकारात्मक रही और निवेश को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। इस बीच जर्मनी में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीक के क्षेत्र में भी प्रगति हुई और करीब 200 करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति बनी, जिससे प्रदेश में उन्नत रेलवे तकनीक सहयोग को गति मिलने की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश उच्च तकनीक आधारित विनिर्माण के साथ सेवा क्षेत्र को समान प्राथमिकता देते हुए उद्योगों के लिए पारदर्शी और उद्योग–मित्र वातावरण सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को भूमि आवंटन से लेकर संचालन तक हर स्तर पर प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

इन क्षेत्रों पर भी हुई चर्चा

मेडिकल डिवाइस, वस्त्र, चमड़ा और फुटवियर

सेमीकंडक्टर, रक्षा और आईटी/आईटीईएस

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC)

660+ मेगावाट डेटा सेंटर क्षमता

सेवा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को भी नई गति मिलेगी

जर्मनी में प्रत्यक्ष बैठकों के साथ यूके के निवेशकों से डिजिटल माध्यम से हुआ संवाद निवेश कूटनीति के बेहद सकारात्मक स्वरूप का संकेत है। इससे न केवल तकनीकी सहयोग के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि सेवा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को भी नई गति मिलेगी। संभावित निवेश से कौशल आधारित रोजगार सृजित होंगे और स्मार्ट सिटी व डिजिटल सेवाओं के विस्तार के जरिए शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जर्मनी में जारी बैठकों और यूके निवेशकों के साथ बनी सहमति को इसी दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति माना जा रहा है।

मांगों को लेकर राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन ने परिवहन आयुक्त कार्यालय घेरा

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी में गुरुवार को राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति के बैनर तले बड़ी संख्या में ड्राइवरों और वाहन मालिकों ने परिवहन आयुक्त कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुरानी गाड़ियों पर लगाए जा रहे रोड टैक्स की पेनाल्टी को माफ करने और वन टाइम टैक्स नीति में संशोधन की मांग उठाई। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि आर्थिक तंगी और बदलते नियमों के चलते कई वाहन मालिक समय पर टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उन पर भारी पेनाल्टी लगाई जा रही है।

उनका आरोप है कि यह व्यवस्था छोटे वाहन चालकों और मध्यम वर्गीय मालिकों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि वन टाइम टैक्स की वर्तमान नीति को चार भागों में विभाजित किया जाए, ताकि वाहन मालिकों को किस्तों में भुगतान की सुविधा मिल सके। यूनियन का कहना है कि इससे टैक्स जमा करने की प्रक्रिया आसान होगी और वाहन मालिकों को राहत मिलेगी।

लखनऊ के प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ.पी. सी. गुप्ता को भारतीय डिजाइन पेटेंट प्राप्त

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ स्थित प्रख्यात अर्थशास्त्री एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश डॉ. पी. सी. गुप्ता को "AI–Based Device for Business Strategy Planning and Risk Forecasting" शीर्षक से विकसित नवाचार हेतु भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा डिजाइन पंजीकरण प्रमाणपत्र (Indian Design Patent) प्रदान किया गया है। यह पंजीकरण डिजाइन अधिनियम, 2000 एवं डिजाइन नियम, 2001 के अंतर्गत प्रदान किया गया है द्य यह अभिनव डिजाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित उपकरण से संबंधित है, जो व्यवसायिक रणनीति निर्माण (Business Strategy Planning) एवं जोखिम पूर्वानुमान (Risk Forecasting) में सहायक है। यह उपकरण आधुनिक आर्थिक विश्लेषण, डेटा आधारित निर्णय–निर्माण तथा संस्थागत प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस उपलब्धि में डॉ. पी. सी. गुप्ता के साथ अन्य सह–आविष्कारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें डॉ. महेन्द्र कुमार नामदेव, डॉ. मुस्ताक आलम, पूजा उपाध्याय, डॉ. किरण सचदेवा, डॉ. श्वेता सिंह, सुमोना घोष, विशाल मिश्रा, अवधेश यादव एवं अपराजिता श्रीवास्तव शामिल हैं। डॉ. पी. सी. गुप्ता, जो कि लखनऊ के एक सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् एवं अर्थशास्त्री हैं, एवं डॉ. मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री एवं वरिष्ठ अर्थशात्री द्वारा भी अपनी अर्थशास्त्र पर पुस्तकों हेतु सराहना पत्र एवं मार्गदर्शन पा चुके है ने इस उपलब्धि को शिक्षण, अनुसंधान एवं नवाचार के समन्वय का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यह डिजाइन भविष्य में उद्योग, शिक्षा एवं नीति–निर्माण के क्षेत्र में रणनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक एवं प्रभावी बनाएगा। शैक्षणिक एवं बौद्धिक जगत में इस उपलब्धि को अत्यंत गौरवपूर्ण माना जा रहा है। यह न केवल संस्थान बल्कि लखनऊ शहर एवं प्रदेश के लिए भी गर्व का विषय है।

भूल गए गेस्ट हाउस की वो काली रात, मायावती का सपा पर बड़ा हमला-बहुजन समाज के असली दुश्मन हैं समाजवादी

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड की गूंज सुनाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा हमला बोलते हुए उनके चाल, चरित्र और चेहरे को दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी बताया है। मायावती ने साफ शब्दों में कहा कि सपा ने हमेशा बहुजन समाज के महापुरुषों का अपमान किया है और दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझा है। मायावती ने 2 जून 1995 की उस खौफनाक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सपा का दलित विरोधी इतिहास पुराना है। मायावती ने कहा कि 1993 में जब सपा–बसपा का गठबंधन हुआ, तब शर्त थी कि दलितों पर अत्याचार रुकेगा, लेकिन अगले ही दिन 2 जून को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में उन पर जानलेवा हमला कराया गया।

मुलायम सिंह यादव ने अपना रवैया नहीं बदला। 1 जून 1995 को जब बसपा ने समर्थन वापस लिया, तो मायावती ने इसे काली क्रूरता करार दिया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बसपा प्रमुख ने अखिलेश यादव की घेराबंदी करते हुए सवाल पूछा कि सपा आज भले ही दलितों की बात करे, लेकिन उसने हमेशा कांशीराम जी का तिरस्कार किया है। मायावती ने कहा कि सपा सरकार ने कांशीराम जी के नाम पर बने जिलों और संस्थानों के नाम बदल दिए। उन्होंने पूछा कि कांशीराम जी के निधन के बाद सपा सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक तक क्यों नहीं घोषित किया? मायावती ने केवल दलितों ही नहीं, बल्कि मुस्लिमों को भी सपा से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरह सपा के शासनकाल में भी बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें लाखों मुस्लिम परिवार बर्बाद हो गए। मायावती ने गंभीर आरोप लगाया कि सपा अपने भड़काऊ आचरण से भाजपा को राजनीतिक जमीन तैयार करके देती है। उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा एक–दूसरे की जरूरत बनकर राजनीति करते हैं, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। मायावती ने अंत में कहा कि आज उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा का राज है, तो उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी ही है। सपा की जातिवादी और सांप्रदायिक राजनीति के कारण ही आज बहुजन समाज और मुस्लिम वर्ग त्रस्त है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सपा के इस बहुरूपिया चेहरे को पहचानें और सावधान रहें।

मानव सम्पदा पोर्टल को लेकर प्रदेश स्तरीय विरोधसभा

बंद मानव सम्पदा पोर्टल के कारण कर्मचारी परेशान

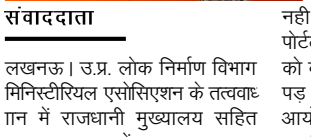

संवाददाता

लखनऊ। उ.प्र. लोक निर्माण विभाग मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के तत्वावधान में राजधानी मुख्यालय सहित जनपद मुख्यालयों पर मानव सम्पदा पोर्टल खोले जाने की मांग को लेकर विरोध समाए की गई। वक्ताओं ने इस दौरान अपने सम्बोधन में कहा कि मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल–अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज करने हेतु उवप्रव शासन द्वारा आदेश जारी किए गए उक्त विवरण को 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर भरा जाना था। दिनांक 31 जनवरी 2026 के बाद उक्त पोर्टल के बन्द हो जाने के कारण हमारे कई विभागीय अधिकारीध्कर्मचारी द्वारा वर्तमान में उपरोक्त विवरण नही भर पा रहे हैं। मानव सम्पदा पोर्टल बंद होने के कारण कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी मुख्यालय में आयोजित सभा में जे.पी. पाण्डेय प्रान्तीय महामंत्री ने बताया कि 12 फरवरी 2026 को उक्त पोर्टल को एक माह से लिए पुनः खोलने हेतु सम्पूर्ण उ.प्र. के राज्य कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री को सम्बन्धित जनपद के जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया था ।अब होली व ईद इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार होने के कारण प्रदेश भर में कार्यरत कर्मचारियों के सामने वेतन न मिलने के कारण अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ना स्वाभाविक है। इस कारणवश मानव सम्पदा पोर्टल पर सम्पत्ति का विवरण दर्ज कराने हेतु, पोर्टल को पुनः खोले जाने के अलिए आज भोजनावकाश के समय दोपहर 2.00 बजे से 2.30 बजे तक प्रदेश के समस्त कार्यालयों पर सामूहिक रूप से एकत्रित होकर कर्मचारियों द्वारा आम सभा कर प्रदेश सरकार से तत्काल प्रभाव से पोर्टल खोले जाने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन की इस मांग को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ व उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ व उ.प्र.फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन्स का समर्थन मिला है।

संक्षिप्त

दो नाबालिग सहित 3 चोर गिरफ्तार, दो घरों में चोरी का खुलासा

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के मड़ियांव क्षेत्र में बंद घरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में दो नाबालिग हैं। तीनों ऑटो से घूमकर रेकी करने के बाद घटना को अंजाम देते थे। आरोपियों के कब्जे से सोने–चांदी के जेवरात और नकदी बरामद हुई है। इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा ने बताया कि पुलिस टीमें गश्त पर थी इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि प्रधान मैरिज लॉन कट से बालाजी इन्क्लेव जाने वाले रास्ते पर तीन संदिग्ध व्यक्ति एक ऑटो में बैठे हैं।

सूचना पर टीम रवाना हुई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जैसे ही ऑटो को घेरकर रोकने की कोशिश की, उसमें बैठे लोग भागने का प्रयास करने लगे। घेराबंदी कर पुलिस ने ऑटो समेत तीनों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान हरिओमनगर नौबस्ता निवासी सोनू मौर्या (21) और दो नाबालिगों के रुप में हुई। पुलिस ने भागने की वजह पूछी तो गुमराह करने लगे। इसके बाद पुलिस ने कड़ाई की तो तीनों ने कबूल किया।

भाजपा प्रदेश संगठन में बढ़ेगी महिलाओं, दलित और ओबीसी की भागेदारी, होली के बाद होगा ऐलान

संवाददाता

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान होली के बाद किया जा सकता है। पार्टी संगठन में इस बार नए चेहरों को मौका देने की तैयारी है। खासतौर पर महिलाओं, दलितों और ओबीसी वर्ग की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी मिलने के बाद नई टीम की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। लंबी संगठनात्मक प्रक्रिया के बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में नई कार्यकारिणी लगभग तैयार है। बचे हुए कई मंडल अध्यक्षों के नाम मंगलवार और बुधवार को घोषित कर दिए गए हैं। बाकी जिलाध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा भी इसी सप्ताह होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह केंद्रीय नेतृत्व से लगातार चर्चा कर रहे हैं। ज्यादातर नामों पर सहमति बन चुकी है। अंतिम मंजूरी मिलते ही नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी नई टीम में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। पूर्वांचल के साथ–साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं को भी उचित प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया जा रहा है।

पार्टी का लक्ष्य नए और सक्रिय चेहरों को आगे लाकर संगठन को मजबूत करना है। सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन के जरिए भाजपा आगामी चुनावों के लिए अपनी तैयारियों को और मजबूत करना चाहती है। इसलिए जिला कार्यकारिणी के गठन में भी महिलाओं, दलितों और ओबीसी को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर निगम में बड़ा खुलासा, 23 अफसरों पर गिरी गाज, फर्जी निस्तारण का घोटाला उजागर

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम से जुड़ा एक बड़ा प्रशासनिक खुलासा सामने आया है। लखनऊ नगर निगम के 23 अधिकारियों पर 300 से अधिक शिकायतों के फर्जी निस्तारण का आरोप लगा है। मामले के सामने आने के बाद निगम में हड़कंप मच गया है। जांच में पता चला है कि कई मामलों में बिना काम किए ही सड़क मरम्मत पूरी दिखा दी गई। सीवर लीकेज की शिकायतें भी कागजों में निपटा दी गईं, जबकि जमीनी स्तर पर समस्याएं जस की तस बनी रहीं। हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी म्यूटेशन से जुड़े मामलों में भी भारी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। शिकायतों का समाधान दिखाकर फाइलें बंद कर दी गईं, जबकि संबंधित नागरिकों को राहत नहीं मिली। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद जांच में तेजी आई। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने सभी 23 अधिकारियों को नोटिस जारी कर दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।

जोनल अधिकारियों से लेकर चीफ इंजीनियर और एक्सईएन स्तर के अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं। विशाख जी के पत्र के बाद मामले में कार्रवाई की रफ्तार और तेज हो गई। फर्जी निस्तारण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है और दोषी अधिकारियों की सूची अंतिम चरण में बताई जा रही है। नगर निगम शासन को विस्तृत रिपोर्ट भेजने की तैयारी में है। शहर में प्रशासनिक सख्ती के बीच बड़े फेरबदल के संकेत भी मिल रहे हैं।

वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं देना चाहती केन्द्र सरकार

उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरेगी पार्टी : चेतन शर्मा
अभिनव भारत पार्टी के अधिवेशन में जुटे देश के साधु–संत

संवाददाता

लखनऊ। क्रान्तिकारी स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर आज यहां इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुये अभिनव भारत पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा करते हुये कहा है कि केन्द्र सरकार वीर सावरकर को भारत–रत्न देने के लिये गंभीर नहीं है। अधिवेशन में पार्टी के सर्वसम्मति से नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि वीर सावरकर ने अपने युवावस्था में ही अभिनव भारत संगठन की स्थापना कर पराधीन भारत में क्रान्ति की ज्वाला प्रज्जवलित की थी, उन्होंने केवल स्वतंत्रता का स्वप्न नहीं देखा बल्कि उसके लिये कालकोठरी में अमानवीय यातनायें सही। अंडमान की सेल्युलर जेल की दीवारें आज भी उस तप, त्याग और तेज की साक्षी है, ऐसे व्यक्तित्व को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी वीर सावरकर को भारत रत्न दिये जाने को लेकर कह चुके है कि सावरकर के योगदान को देखते हुये यदि उन्हें भारत–रत्न मिलता है तो इससे भारत–रत्न का सम्मान होगा। श्री शर्मा ने बताया कि अभिनव पार्टी ने पिछले वर्ष वीर सावरकर को भारत–रत्न दिलाने की मांग को लेकर देशभर में सावरकर सम्मान यात्रा निकालकर देश की राष्ट्रपति के नाम सम्बोधित आठ सौ ज्ञापन देश के विभिन्न हिस्सों से दिये गये, लेकिन इसके बावजूद केन्द्र सरकार इस संबंध में कोई विचार नहीं कर रही है, इसके लिये पार्टी निरन्तर संघर्ष करती रहेगी। श्री शर्मा ने अधिवेशन में पारित प्रस्तावों को लेकर कहा कि देश में गाय की सुरक्षा के लिये माता का दर्जा देने के साथ–साथ उसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाये, तभी जाकर देश में गाय माता को बचाया जा सकता है। गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा केवल भावनात्मक निर्णय नहीं होगा बल्कि यह एक ठोस कानूनी संरक्षण का मार्ग प्रशस्त होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन शर्मा ने कहा कि अभिनव भारत पार्टी राज्य के चुनावी रणभूमि में उतरने के लिये पूरी तरह तैयार है, और लगभग तीन सौ सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। चुनावी रणनीति को लेकर अभिनव भारत पार्टी जल्द ही अन्तिम रूप देकर उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर जायेगी। इससे पहले इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान में अधिवेशन का शुभारम्भ भारत माता की स्तुति और वन्देभारत गीत के साथ दीप प्रज्जवलित कर हुआ। इस मौके पर प्रमुख रूप से मालेगांव मामले में बरी हुये मेजर रमेश उपाध्याय, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री कम्प्यूटर बाबा, पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री ममता झा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. नीलेन्द्र गौतम, श्रीमती चित्रा दलाल, स्वरूपानंद महाराज के शिष्य त्रिभुवन दास, कार्तिक गिरी, सर्वेश मिश्रा, महामण्डलेश्वर अमरेशानन्द गिरी सहित देशभर से आये पार्टी के कार्यकर्ता एवं प्रतिनिधि मौजूद थे।

हर जिले में 100 तालाबों को मॉडल के रूप में विकसित करेगी योगी सरकार

ग्रे वाटर और प्लास्टिक से मुक्त होंगे मॉडल तालाब
मॉडल तालाब बनाने के लिए चलेगा `मेरा तालाब मेरी जिम्मेदारी' अभियान
प्रथम चरण में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में चलेगा अभियान
पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य के लिए विशेष पहल
जल की गुणवत्ता में होगा सुधार, मच्छरजनित रोगों में आएगी कमी

बीएनई

गोरखपुर। प्रदेश की योगी सरकार ने तालाबों के पर्यावरणीय व सामाजिक महत्व को नए सिरे से स्थापित करने का निर्णय लिया है। पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य के लिए विशेष पहल करते हुए सरकार प्रदेश के सभी जिलों में 100–100 तालाबों को 'मॉडल तालाब' के रूप में विकसित करने जा रही है। ये मॉडल तालाब ग्रे वाटर और प्लास्टिक से मुक्त होंगे। इससे जल की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा मच्छरजनित रोगों में कमी आएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब केवल जल संग्रहण के साधन ही नहीं हैं बल्कि ग्राउंड वाटर (भू–जल) रिचार्ज, सिंचाई, जैव विविधता संरक्षण और सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण केंद्र भी रहे हैं। गांवों में प्लास्टिक अपशिष्ट तथा ग्रे वाटर (स्नान, रसोई और कपड़े धोने से निकलने वाला जल) बिना शोधन या उपचार के सीधे तालाब में प्रवाहित कर देने से ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में तालाबों को प्लास्टिक अपशिष्ट और ग्रे वाटर मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत पंचायती राज विभाग ने मॉडल तालाब विकसित करने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। इस कार्ययोजना के मुताबिक हर जिले के 100 तालाब 'मेरा तालाब मेरी जिम्मेदारी' अभियान से जोड़कर मॉडल स्वरूप में निखारे जाएंगे। अभियान को लेकर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के निदेशक की तरफ से सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को सर्कुलर जारी किया गया है। मॉडल तालाब विकसित करने के क्रम में प्रथम चरण का अभियान 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में चलेगा। ऐसे गांव में तालाब का चयन कर यह देखा जाएगा कि कितने परिवारों का ग्रे वाटर तालाब में गिर रहा है। कितनी नालियों से पानी तालाब में प्रवाहित किया जा रहा है। प्रतिदिन औसतन कितना प्लास्टिक अपशिष्ट तालाब में डाला जा रहा है। जिस तालाब का चयन किया जाएगा, उसका बीओडी (बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैविक ऑक्सीजन मांग) भी चेक किया जाएगा ताकि तालाब को मॉडल स्वरूप में विकसित करने के बाद तुलनात्मक सुधार का पता लगाया जा सके। जिला पंचायतराज अधिकारी नीलेश प्रताप सिंह बताते हैं कि मॉडल तालाब विकसित करने के लिए चयनित

तालाब के चारों ओर नो प्लास्टिक जोन घोषित किया जाएगा। साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत से तालाब में प्लास्टिक अपशिष्ट न फेकने का प्रस्ताव पारित कराया जाएगा। तालाब में गिरने वाली नालियों पर प्लास्टिक ट्रैप वाली जाली, फिल्टर चौंबर लगाया जाएगा। इससे प्लास्टिक और गंदगी तालाब में जाने से पहले ही रुक जाएगी। इसी तरह ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे ग्रे वाटर का प्रवाह सीधे तालाब में न हो। इसके लिए नाली के अंत में बायो फिल्टर सिस्टम लगाया जाएगा। इसमें कंकड़, रेत के इस्तेमाल के अलावा केली और केना (एक किस्म का खरपतवार) के पौधे लगाए जाएंगे। इस उपचार से पानी प्राकृतिक रूप से शुद्ध होकर तालाब में जाएगा। प्लास्टिक और ग्रे वाटर से जुड़े रोकथाम की निगरानी समुदाय स्तर पर की जाएगी। मॉडल तालाब विकसित होने से तालाब प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा, ग्रे वाटर का स्थायी समाधान होगा। जल के स्वच्छ और सुरक्षित होने से ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में आशातीत सुधार होगा।

स्मार्टफोन निर्यात 30 अरब डॉलर के पार : दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनता भारत, 2025 में 30 करोड़ फोन का उत्पादन

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। देश में 2025 में हुए कुल निर्यात में स्मार्टफोन का दबदबा रहा। इस अवधि में स्वदेशी निर्मित 30 अरब डॉलर मूल्य से अधिक का स्मार्टफोन निर्यात किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी साझा करते हुए कहा, भारत अब दुनिया का स्मार्टफोन विनिर्माण केंद्र बनता जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी–दिसंबर, 2025 के दौरान देश का स्मार्टफोन निर्यात 30 अरब डॉलर पहुंच गया। वहीं, वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान करीब 60 अरब डॉलर (5.5 लाख करोड़ रुपये) के स्मार्टफोन का उत्पादन हुआ, जबकि निर्यात 22 अरब डॉलर (करीब दो लाख करोड़ रुपये) रहा। देश से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का कुल निर्यात 2025 के दौरान 44 अरब डॉलर (चार लाख करोड़ रुपये) के पार पहुंच गया। इस साल चार सेमीकंडक्टर संयंत्रों में उत्पादन शुरू करने के बाद इसके निर्यात में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बाजार शोध संस्था काउंटरपॉइंट रिसर्च के सह–संस्थापक एवं शोध उपाध्यक्ष नील शाह ने कहा, एपल ने चीन पर अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद भारत में विनिर्माण बढ़ाकर देश को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी है।

भारत में 2025 में 30 करोड़ स्मार्टफोन का उत्पादन होने का अनुमान है और हर चार में से एक स्मार्टफोन का निर्यात किया गया। उच्च औसत विक्रय मूल्य (एएसपी) वाले अमेरिकी बाजार में एपल, सैमसंग और मोटोरोला की मजबूत मांग ने निर्यात मूल्य को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा दिया। एपल ने रिकॉर्ड 50 लाख आईफोन की आपूर्ति की इंटरनेशनल डाटा कॉरपोरेशन (आईडीसी) के वर्ल्डवाइड क्वार्टरली मोबाइल फोन ट्रैकर रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 की तीसरी तिमाही में एपल ने घरेलू बाजार में 50 लाख आईफोन की आपूर्ति की, जो किसी भी तिमाही का उच्चतम स्तर है। रिपोर्ट के मुताबिक, एपल प्रीमियम (53,000–71,000 रुपये की कीमत वाले स्मार्टफोन) और सुपर–प्रीमियम सेगमेंट (71,000 रुपये से अधिक कीमत वाले) दोनों में सबसे आगे है। इसने सितंबर तिमाही के दौरान भारत के स्मार्टफोन मार्केट की वृद्धि की रफ्तार बढ़ाई।

होली पर किसानों के जीवन में खुशहाली का रंग भरेगी योगी सरकार

त्योहार पर किसानों को फिर मिलेगा कृषि यंत्रों का तोहफा
अनुदान पर कृषि यंत्र पाने के लिए किसानों को चार मार्च तक करना होगा आवेदन
कृषि विभाग की वेबसाइट www.agridarshan.up.gov.in पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन
वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनवरी तक 7777 कृषि यंत्र, 51 कस्टम हायरिंग सेंटर एवं 64 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के बिल पोर्टल पर हुए अपलोड

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। योगी सरकार होली पर किसानों के जीवन में 'समृद्धि' का रंग घोलेगी। उप्र कृषि विभाग द्वारा त्योहार पर किसानों को कृषि यंत्र का तोहफा देने की पहल की गई है। अनुदान पर मिलने वाले कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग प्रारंभ हो गई है, जो चार मार्च तक चलेगी। किसानों को विभाग की वेबसाइट www.agridarshan.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

चार मार्च तक इन यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं किसान

कृषि विभाग द्वारा संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक, कृषि ड्रोन, अन्य एकल कृषि यंत्र तथा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन–सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू योजना के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन के अन्य एकल कृषि यंत्र एवं अन्य योजनाओं के कृषि यंत्र/कृषि रक्षा उपकरण के आवेदन चार मार्च तक किए जा सकते हैं। त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के तहत बैच ड्रायर एवं मेज सेलर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन करनी होगी बुकिंग

कृषि यंत्रों की बुकिंग या आवेदन विभाग की वेबसाइट www.agridarshan.up.gov.in पर ऑनलाइन करनी होगी। इस लिंक पर किसान कॉर्नर के अंतर्गत यंत्र बुकिंग प्रारंभ पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यंत्रों से जुड़ी समस्त जानकारी व अनुदान प्रक्रिया पर इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। लाभार्थियों का चयन/बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र खरीद कर उसकी रसीद व फोटो 10 दिन के भीतर www.agridarshan.up.gov.in या upyantratraking.in अपलोड करना होगा।

2017 से 2025 तक लगभग तीन लाख कृषि यंत्रों का वितरण

2017–18 से 2025 तक उत्तर प्रदेश में लगभग तीन लाख कृषि यंत्रों का वितरण किया गया। इसमें 2.31 लाख एकल कृषि यंत्र, 8405 कस्टम हायरिंग सेंटर, 7351 फॉर्म मशीनरी बैंक आदि प्रमुख हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंतर्गत जनवरी तक 7777 कृषि यंत्र, 51 कस्टम हायरिंग सेंटर एवं 64 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित के बिल पोर्टल पर अपलोड हुए।

"छत्तीसगढ़ की विभूतियाँ : पद्म पुरस्कार प्राप्त महान व्यक्तित्वों की प्रेरक यात्रा - एक फोटो प्रदर्शनी"

फोटो प्रदर्शनी 2 मार्च एवं 03 मार्च 2026 तक कला वीथिका

बीएनई

रायपुर। छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष के अवसर पर क्लाउड एवं संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ के द्वारा "छत्तीसगढ़ की विभूतियाँ : पद्म पुरस्कार प्राप्त महान व्यक्तित्वों की प्रेरक यात्रा – एक फोटो प्रदर्शनी" दो दिवसीय विशेष फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी 2 मार्च 2026 एवं 03 मार्च 2026 तक कला वीथिका, महंत घासीदास संग्रहालय परिसर, रायपुर में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से रात्रि 7 बजे तक आयोजित होगी। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जीवन–यात्रा, संघर्ष, उपलब्धियों एवं समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करना है, जिन्हें देश के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस संकलित प्रदर्शनी में महान विभूतियों के व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक चित्र के साथ संक्षिप्त विवरण भी प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे आगंतुकों को उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों और प्रेरक प्रसंगों की जानकारी मिल सके। क्लाउड एवं संस्कृति विभाग का मानना है कि ऐसे आयोजन न केवल समाज को अपने गौरवशाली अतीत से परिचित कराते हैं, बल्कि युवा पीढ़ी को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से यह संदेश दिया जाएगा कि समर्पण, परिश्रम और समाजसेवा की भावना से व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकता है। प्रदर्शनी में शिक्षा, कला, साहित्य, लोकसंस्कृति, समाजसेवा, विज्ञान तथा अन्य विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पद्म सम्मानित महानुभावों की उपलब्धियों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। संस्कृति संचालक विवेक आचार्य (आई. एफ. एस।)के अनुसार यह प्रदर्शनी समाज के सभी वर्गों के लिए प्रेरणास्रोत सिद्ध होगी और छत्तीसगढ़ की विभूतियों के प्रति सम्मान एवं गौरव की भावना को और अधिक सशक्त बनाएगी। उमेश मिश्रा उपसंचालक संस्कृति ने कहा यह आयोजन प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना को सुदृढ़ करने और राज्य की उपलब्धियों पर गर्व की अनुभूति कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता दीपेंद्र दीवान के द्वारा विद्यालयों, महाविद्यालयों, शोधार्थियों, कला प्रेमियों तथा आम नागरिकों से इस प्रदर्शनी में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की गई है।

संक्षिप्त

पर्यटन को विकास का इंजन बनाने की तैयारी, जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ाकर 10 फीसदी करने का लक्ष्य

एजेंसी/नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पर्यटन अब राष्ट्रीय विकास का एक अहम स्तंभ बन चुका है। उन्होंने सरकार के उस विजन को रेखांकित किया, जिसके तहत पर्यटन क्षेत्र का जीडीपी में योगदान मौजूदा 6% से बढ़ाकर 10% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। शेखावत ने यह बात नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में आयोजित साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज (SATTE) के 33वें संस्करण में कही। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए शेखावत ने कहा कि पर्यटन न केवल आर्थिक वृद्धि को गति देता है।

कन्नौज : नई शिक्षा नीति अपनाएं, वॉलंटियर सेवा से जुड़कर बनें विकसित भारत की ताकत

विकसित भारत युवा संसद में राज्यमंत्री असीम अरुण का युवाओं से आह्वान

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज। युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ कन्नौज स्थित पी.एस.एम. डिग्री कॉलेज में गुरुवार को विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने किया। युवा संसद का उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान की गरिमा और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना है। कार्यक्रम में राज्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और वे संविधान व कानून के दायरे में रहकर कार्य करते हैं। आज देश में हर निर्णय संविधान के अनुसार लिया जाता है और सभी नागरिक कानून की नजर में समान हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गुंडागर्दी, अवैध कब्जा और मारपीट जैसी घटनाएं लोकतंत्र के खिलाफ हैं। कानून तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

'मेरा युवा भारत' पोर्टल पर पंजीकरण का आह्वान

उन्होंने नई शिक्षा नीति पर जोर देते हुए युवाओं से समाज सेवा और वॉलंटियर कार्यों में आगे आने की अपील की, जिससे विकसित भारत बना सकें। वहीं आधुनिक तकनीक से पुनर्जीवित तीन तालाब छात्रों के लिए सीख हैं। उन्होंने युवाओं से 'मेरा युवा भारत' पोर्टल पर पंजीकरण कर योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया ने भी युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में छात्र–छात्राओं ने लोकतंत्र, संविधान और विकसित भारत पर अपने विचार रखे।

22 एक्सप्रेस-वे के जाल से बदलेगा यूपी का भविष्य, औद्योगिक क्रांति की ओर कदम

सात चालू, तीन निर्माणाधीन और 12 प्रस्तावित परियोजनाओं से बनेगा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस–वे नेटवर्क
औद्योगिक माल ढुलाई को मिलेगी गति, लॉजिस्टिक लागत में आएगी कमी

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है, जिसके पास सबसे बड़ा एक्सप्रेस–वे का नेटवर्क होगा। फरवरी 2026 तक प्रदेश में कुल 22 एक्सप्रेस–वे का नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। इनमें सात एक्सप्रेस–वे पूरी तरह संचालित हैं, तीन निर्माणाधीन हैं और 12 विभिन्न चरणों में प्रस्तावित या स्वीकृत हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद प्रदेश के लगभग सभी जिलों को उच्च गुणवत्ता वाली कनेक्टिविटी से जोड़ा जा सकेगा। इससे औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को अभूतपूर्व गति मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जापान दौरे पर प्रदेश में एक्सप्रेस–वे के किनारे 27 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने को लेकर कार्यवाही प्रारंभ करने की बात कही। साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री लीडर्स से प्रदेश में निवेश का आह्वान किया। वर्तमान में पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे, यमुना एक्सप्रेस–वे, दिल्ली–मेरठ रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सीधी और तेज कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित कर रहे हैं। निर्माणाधीन परियोजनाओं में गंगा एक्सप्रेस–वे को सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना माना जा रहा है।

एक्सप्रेस–वे, नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस–वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे पूरी तरह चालू हैं। ये एक्सप्रेस–वे न केवल प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ लगभग 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस–वे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। इसके अलावा लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेस–वे समेत अन्य परियोजनाएं भी निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। प्रस्तावित एक्सप्रेस–वे में विंध्य एक्सप्रेस–वे, जिसकी लंबाई लगभग 320 किलोमीटर है और जो प्रयागराज से सोनभद्र को जोड़ेगा, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गोरखपुर–शामली एक्सप्रेस–वे सहित अन्य लिंक परियोजनाएं प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्य औद्योगिक धारा से जोड़ने का माध्यम बनेंगी।

एक्सप्रेस–वे नेटवर्क से औद्योगीकरण को मिलेगी नई दिशा

विस्तृत एक्सप्रेस–वे नेटवर्क, औद्योगिकरण को नई दिशा देगा। बेहतर सड़कों और तेज परिवहन से औद्योगिक माल ढुलाई की लागत में कमी आएगी और समय की बचत होगी। इससे विनिर्माण इकाइयों, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। एक्सप्रेस–वे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर, औद्योगिक पार्क और निवेश क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, जिससे निवेशकों को भूमि, परिवहन और बाजार तक त्वरित पहुंच उपलब्ध हो सके।

लॉजिस्टिक दक्षता से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता

लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार से प्रदेश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। निर्यात उन्मुख उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ने से क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में मदद मिलेगी।

एक्सप्रेस–वे आधारित विकास मॉडल से अर्थव्यवस्था को गति

एक्सप्रेस–वे आधारित विकास मॉडल से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार सृजन में भी बढ़ोतरी होगी। निर्माण कार्यों से प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, जबकि औद्योगिक निवेश से दीर्घकालिक रोजगार सृजन की उम्मीद है।

भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए क्या करना होगा? पाकिस्तान लगाएगा आखिरी दांव!

एजेंसी

नई दिल्ली। टी20 विश्वकप 2026 अब एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। सुपर–8 चरण के आखिरी कुछ मैच बचे हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने की जंग दिलचस्प हो चली है। यह जंग कितनी मुश्किल है, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि सुपर–8 राउंड के छह मैचों के बाद अब तक सिर्फ एक ही टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकी है। इंग्लैंड की सीट पक्की हो चुकी है। वहीं, तीन अन्य जगहों के लिए अभी पांच टीमों के बीच टक्कर है। सुपर–8 ग्रुप–1 से अभी तक किसी टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, जबकि ग्रुप–2 से इंग्लैंड की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। क्या होगा भारत–वेस्टइंडीज वर्चुअल नॉकआउट? टीम इंडिया भी सुपर–8 राउंड में जूझ रही है। दरअसल, सुपर–8 चरण में भारत की शुरुआत ही बेहद खराब रही। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रन की करारी हार ने भारतीय टीम को मुश्किल हालात में ला खड़ा किया है। कप्तान सूर्यकुमार की अगुवाई वाली टीम का नेट रन रेट –3.800 तक गिर गया है।

'हल्के–फुल्के रोल करना चाहती हूं', तापसी पन्नू ने टाइपकास्ट किए जाने पर उठाए सवाल, कहा– धारणा तोड़नी पड़ती है

एजेंसी

तापसी पन्नू को अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'अस्सी' के लिए प्रशंसाएं मिल रही हैं। फिल्म को भी क्रिटिक्स द्वारा काफी सराहा जा रहा है। हालांकि, हर बार की तरह इस बार भी अच्छा कंटेंट और तारीफों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस धीमी रफ्तार से ही आगे बढ़ रही है। इस बीच तापसी पन्नू ने एक ही तरह के किरदार के लिए एक ही तरह के कलाकारों को चुनने के मुद्दे पर सवाल उठाया। तापसी की अनुभव सिन्हा के साथ ये तीसरी फिल्म है, इससे पहले दोनों 'मुल्क' और 'थप्पड़' में भी साथ काम कर चुके हैं। कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता गलाट्टा प्लस के साथ बातचीत के दौरान तापसी पन्नू ने बताया कि उन्होंने कई प्रमुख निर्देशकों से उनकी फिल्मों में बार–बार दोहराए जाने वाले कास्टिंग विकल्पों के बारे में सवाल किए हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि यह मुश्किल है। मेरे लिए नहीं, बल्कि लोगों के लिए यह कल्पना करना मुश्किल है क्योंकि हम अपनी कल्पना के आरामदायक दायरे में इतने खुश रहते हैं। 'ठीक है, यह इस तरह की भूमिका है, तो यह ठीक रहेगी।' कोई भी लीक से हटकर सोचना नहीं चाहता। जब मैं यहां के कुछ शीर्ष निर्देशकों से मिलने जाती हूं, तो उनसे मेरी बातचीत होती है। सबसे पहले मुझे यह धारणा तोड़नी पड़ती है कि मैं ऐसी फिल्में करने में सहज हूं, जिनमें मैं मुख्य भूमिका में नहीं हूं। यानी कि कहानी मेरी नहीं है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743